GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *124
TO BE ANSWERED ON 19/12/2022

Underutilisation of coal mines in the country

*124. **Smt. Ranjeet Ranjan**:

Will the Minister of **COAL** be pleased to state:

(a) whether Government is aware that as of October 2022, only two thirds of the country's coal mines are being utilised to their capacity;

(b) whether Government plans to develop 99 new coal projects with a production target of 427 million tonnes per year, despite the underutilisation of the existing coal mines;

(c) whether Government has examined or intends to examine the issue of underutilisation of these existing coal mines;

(d) if so, the details thereof, including measures to address the aforementioned issue of underutilisation; and

(e) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES
(SHRI PRALHAD JOSHI)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

Statement in Reply to the Rajya Sabha Starred Question No. 124 to be answered on 19.12.2022 regarding Underutilization of coal mines in the country

(a): Coal mines are operated as per the approved mining plan. Considering last 5 years average, CIL's overall system capacity utilization is near about 80%. The capacity utilization of SCCL has been near about 82-90% and capacity utilization of NLCIL has been near about 85% - 100% as per mine plan.

(b): As per demand projections, coal mines are planned and its operations run to ensure energy security of the country. Development of new mines are also required towards Atmanirbhar Bharat to reduce import dependence. Coal demand of 1500 MTPA is projected by various agencies by 2030. Some redundancy in mines' capacity has to be in-built to sustain production at optimum levels when faced with unforeseen and unavoidable situations, such as adverse weather conditions, local & operational problems, land acquisition, geological surprises and variations etc.

(c) to (e): Coal mines are running at optimal capacity as per their mining plans. Operations of coal mines are monitored by the Government on regular basis.

*****

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *124
जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

देश में कोयला खदानों का कम दोहन

***124. श्रीमती रंजीत रंजन:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अक्तूबर 2022 तक देश की केवल दो तिहाई कोयला खदानों का ही उनकी क्षमता के अनुरूप उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार मौजूदा कोयला खदानों को कम उपयोग में लाए जाने के बावजूद 427 मिलियन टन प्रति वर्ष के उत्पादन लक्ष्य के साथ 99 नई कोयला परियोजनाओं को विकसित करने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार ने इन मौजूदा कोयला खदानों के कम दोहन किए जाने के मुद्दे की जांच की है या जांच करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो कम दोहन संबंधी उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए किए जा रहे उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
<u>संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री</u>
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'देश में कोयला खदानों का कम दोहन' के संबंध में श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा दिनांक 19.12.2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *124 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : कोयला खानों का प्रचालन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाता है। पिछले 5 वर्षों के औसत को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल का कुल प्रणाली क्षमता उपयोग लगभग 80% के करीब है। खान योजना के अनुसार एससीसीएल का क्षमता उपयोग लगभग 82-90% और एनएलसीआईएल का क्षमता उपयोग लगभग 85% - 100% के करीब रहा है।

(ख) : मांग अनुमानों के अनुसार, कोयला खानों की योजना बनाई जाती है और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनका प्रचालन किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नई खानों का विकास भी आवश्यक है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2030 तक कोयले की 1500 एमटीपीए मांग का अनुमान लगाया गया है। मौसम की प्रतिकूल दशाएं, स्थानीय और प्रचालनात्मक समस्याएं, भूमि अधिग्रहण, अप्रत्याशित भू-वैज्ञानिक घटनाएं और परिवर्तन आदि जैसी अप्रत्याशित और अपरिहार्य स्थितियों का सामना करने पर इष्टतम स्तर पर उत्पादन बनाए रखने के लिए खान की क्षमता में कुछ अतिरिक्तता अंतर्निहित होनी चाहिए।

(ग) से (ङ): कोयला खानें अपनी खनन योजनाओं के अनुसार इष्टतम क्षमता पर चल रही हैं। कोयला खानों के प्रचालन की सरकार द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

*****

श्रीमती रंजीत रंजनः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आप देखें, तो जो कोयला खदानें अभी विकसित हो रही हैं, उनसे कम-से-कम 165 गाँवों को विस्थापित करने और लगभग 87,630 परिवारों को प्रभावित करने का खतरा है, जिनमें से 41,508 परिवार उन क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर प्रमुख आबादी आदिवासियों की है। इसमें लगभग 22,686 हेक्टेयर कृषि की भूमि है और 19,287 हेक्टेयर जंगल को भी खतरा है। ऐसे में, हम देश की खदानों में सिर्फ दो-तिहाई क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं और कुछ बड़ी खदानों में सिर्फ एक परसेंट क्षमता का उपयोग हो रहा है। मैं आपके आन्सर से सैटिस्फाइड नहीं हूँ। ...(**व्यवधान**)... नई खदानों में हमारे लाखों आदिवासी भाई ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः रंजीत रंजन जी, प्लीज़ आप ब्रीफ्ली क्वेश्चन पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, मैं क्वेश्चन पर ही आ रही हूँ। ...(**व्यवधान**)... उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जल, जंगल, जमीन, यह उनके लिए रोज़ी-रोटी का सवाल है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आज जो मौजूदा खदानें हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, basically, I do not agree with the so-called report which the hon. Member is mentioning. That report is neither credible nor reliable. कोल इंडिया और हमारे पीएसयूज़ के पास जो कोयले की खदानें हैं, यह उन्हें लेकर कैल्कुलेट किया गया है। हमारे पास लगभग 328 माइन्स हैं । It has been calculated on the basis of PRC. पीआरसी सभी में अचीव नहीं होता है। पीआरसी वैदर के कारण, लैंड ऐक्विज़िशन के कारण, नॉन-वायबिलिटी के कारण or for various other reasons प्रभावित होता है और कभी-कभी तो पीआरसी अचीव ही नहीं होता है। इस कारण से, ये जो कर रहे हैं, this is not an acceptable report. Ultimately, it is the question of the energy security of the country. हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को देखना है। जहाँ तक हमारे प्रोडक्शन का सवाल है, in 2014, it was 566 million tonnes. हमारे माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, this year, our total production will be 900 million tonnes, which means, all our PSUs are producing to the optimum level. For example, Coal India's average is around 85 per cent; SCCL's average is around 90 per cent, and, regarding Neyveli Lignite Corporation, where we have given the coal mines also -- it is including lignite -- its average is nearly 100 per cent. Our requirement by 2030 will be 1,500 million tonnes. For that we have to scale up our production. Sir, in the previous regime, they did not produce. There were only scams. Today, we are producing and we are ensuring the energy security for India. For that, coal is needed, and, this is what I would like to mention.

I would once again say that the report which she is mentioning is neither credible nor reliable. I am very clear on this.

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, मैं उन्हें ऑथैंटिक डेटा लाकर दूँगी।

मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है कि 2021-22 में भारत का कोयला आयात 208.93 मिलियन टन था, जिसकी कुल कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपये हुई। वहीं सितंबर महीने तक कोयला आयात करीब 132 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जिसकी कीमत 2.3 लाख करोड़ पहुंच गई है। आप यहाँ आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी इतने बड़े स्तर पर कोयले का आयात कर रहे हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि हम कोयले के मामले में किस साल तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, धन्यवाद। आप एक ही सवाल पूछ सकती हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, दूसरा सवाल भी इसी के साथ है। ...(**व्यवधान**)... हाल ही में एक रिपोर्ट आई है... ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः रंजीत रंजन जी, धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)... आपने एक सवाल पूछ लिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप एक ही सवाल पूछ सकती हैं। ...(**व्यवधान**)... यह दूसरा सवाल है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... दो साल में एक क्वेश्चन आता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः अन्य सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजनः हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें... ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी ...(**व्यवधान**)... एक व्यक्ति तीन सवाल नहीं पूछ सकता है। ...(**व्यवधान**)... हमारे पास और नाम हैं। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, जिन्हें मौका नहीं मिलता है, वे मेरे पास आते हैं। ...(**व्यवधान**)... एक व्यक्ति तीन-तीन सवाल नहीं पूछ सकता है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः क्या आप एक साथ तीन सवाल पूछेंगी? **...(व्यवधान)...** नहीं, प्लीज़। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। Sir, my ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is your third question. Please be clear. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रहलाद जोशीः सर, ये बहुत बड़ी-बड़ी बातों के बारे में बात कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You were supposed to ask only two supplementary questions. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रहलाद जोशीः सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ...(**व्यवधान**)... जो छोटी-छोटी बात करते थे, इनका प्रोडक्शन क्या था? ...(**व्यवधान**)... इनका प्रोडक्शन था 566 million tons in ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप दो क्वेश्चंस पूछ चुकी हैं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी, प्लीज़ आप जवाब दें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I am replying. If you allow, I will give a reply. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RANJEET RANJAN: Sir, please allow me only for thirty seconds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; I am not allowing. ...*(Interruptions)*... माननीय मंत्री जी, प्लीज़ आप जवाब दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रहलाद जोशीः सर, जो बड़ी-बड़ी बातों का ज़िक्र कर रहे हैं, ...(**व्यवधान**)... हमने बात नहीं की है। ...(**व्यवधान**)... हमने जो बात की है, उसको करके दिखलाया है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्य, आपको दो सवाल पूछने का मौका है और आप तीन सवाल पूछ रही हैं। ...(**व्यवधान**)... No, I will not allow. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... माननीय मंत्री जी, आप ब्रीफ्ली जवाब दें। ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजनः *

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, प्लीज़ आप जवाब दें। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती रंजीत रंजनः *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will move to other question now.

श्री प्रहलाद जोशीः सर, यह कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है। They do not have trust on our agencies. They do not have trust on our Army. They do not have trust on our institutions. ***...(Interruptions)...***

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, आप सवाल का जवाब दें। **...(व्यवधान)...**

SHRI PRALHAD JOSHI: This is the situation. ***...(Interruptions)...*** They are trying to rely on a report ***...(Interruptions)...*** एक विदेशी संस्था एक रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में वह यह कहती है कि हमारी जो खदान है, उसका पूरा उपयोग नहीं होता है। **...(व्यवधान)...** मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ कह रहा हूँ। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः प्लीज़, माननीय मंत्री जी। **...(व्यवधान)...**

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I will complete. This is a very important question which she has raised.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please complete.

SHRI PRALHAD JOSHI: On the question that she has raised, I have already told that from each of the mines, on an average, we are utilizing almost 90 per cent of its capacity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

* Not recorded.

SHRI PRALHAD JOSHI: Let me complete, Sir. ...*(Interruptions)*... Our production will be 900 million tonnes, and next year it will be one billion tonnes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI PRALHAD JOSHI: Let me complete, Sir. During their time, the coal was totally under the regime of scams ...*(Interruptions)*... During our regime, under the Prime Minister Modi ji, I would like to assure this House ...*(Interruptions)*... I would like to assure the House that from 2024-25, ...*(Interruptions)*... We will cut the import of thermal coal. ...*(Interruptions)*... This is what I am going to assure to this House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Krishan Lal Panwar; not present. Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA: Thank you, Sir, for giving me this opportunity to ask a very specific question on Odisha. I would first like to thank the hon. Minister that today Odisha is one of the largest States which are producing most of the coal in the country. Mahanadi Coalfields is also doing a tremendous job in Odisha. I would like to know, in terms of Odisha, what are the specific plans and programmes that the hon. Minister has in terms of maximising capacity, utilising capacity of coal in the State of Odisha so that it becomes the largest coal bearing and coal-extraction State in the Country.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I am thankful to hon. Member, Sasmit ji, because the Odisha Government is cooperating as far as coal and other mining sectors are concerned. We had a long discussion with the Odisha Government as far as mining in general and coal mining is concerned. We received many suggestions from them. After receiving those suggestions and having a lengthy discussion with them, we have also changed in certain things and they have also changed in certain things on the process in the State of Odisha. By that, the overall production, which was around 60-65 million tons in 2014, has today reached almost 170 million tons. I would assure that we are going to achieve the target of 200 million tons per year from the Mahanadi Coalfields maximum in one-and-a-half years. This is the plan we have and the detail I will share with you.

On royalty, I would like to tell this. Sir, during the previous regime, allotment was given through a chit route means by a slip route. Now we are auctioning it. We have the most transparent system of auction. पहले कौन से ऑफिस से चिट्ठी आती थी और किसको एलॉट होता था, यह सबको पता है। इसीलिए यह स्कैम बन गया है। ...(**व्यवधान**)... सर,

अभी यह हो रहा है कि हम ट्रान्सपेरेंट सिस्टम में ऑक्शन कर रहे हैं, ट्रान्सपेरेंट सिस्टम में ऑक्शन करने के कारण स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिससे स्टेट स्ट्रेंथन हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... स्टेट के स्ट्रेंथन होने के कारण इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI NEERAJ DANGI: Sir, through you, I would like to know this from the hon. Minister of Coal. Nearly 90 per cent of the proposed coal projects in terms of capacity will be located in the high-risk water zones which will worsen water shortage in the region. What steps will the Government take to mitigate the potential water crisis due to new coal projects in these regions?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I may kindly be allowed to speak in detail. The Environmental Impact Assessment and the EMP are prepared for each project based on the project specific terms of reference recommended by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change which requires a detailed hydrology and hydrogeology impact assessment and management plan based on which EC is granted. Subsidiaries of the CIL are in the process of obtaining No Objection Certificate for abstraction of ground water for each of the project from the Central Ground Water Authority, Ministry of Water Resources of the Government of India. Advance payment of fee is ensured for each project for abstraction of ground water. Clearance is granted based on the detailed hydrological report and ground water. हम जो ये सब करते हैं, इसके साथ ही साथ माइन करने के बाद जो पानी निकलता है, हम वह पानी माइनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। मैं सीआईएल का एग्ज़ाम्पल देता हूं। The objective of the CIL is to attempt maximum utilization of the mine water discharged for the community use. In 2021 and 2022, out of the total 6,440 LCu.m. average mine water discharge, 2,591 LCu.m. of mine water was utilized for own use and 2,826 LCu.m. water was utilized for the community supply, which means some is potable, some is for irrigation and some is for plantation. The entire water is used. Also, plantation is being done. We are taking permission from all the concerned authorities so that there will be no impact on water in the concerned area.

सुश्री सरोज पाण्डेय: उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कोयला खदानों का जो परिचालन होता है, जो राज्यों में स्थापित है, उन राज्यों में केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। राज्य सरकार द्वारा उन अधिकारियों पर अनधिकृत तौर पर दबाव डाला जाता है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अनैतिक कार्यों के लिए लगातार घटनाक्रम हो रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, सवाल पूछें।

सुश्री सरोज पाण्डेयः महोदय, मैं इतना जानना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में अभी कोयला खदानों को लेकर जो घटनाक्रम घटित हुआ है, ...(**व्यवधान**)... जिसको लेकर विपक्षी दल बार-बार उद्वेलित होते हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

सुश्री सरोज पाण्डेयः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ खदानों का क्या विषय रहा है? ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रहलाद जोशीः सर, दबाव डालने की इधर-उधर से कोशिश तो होती है। कई स्टेट्स में ऐसा होता है, लेकिन भारत सरकार इसमें स्पष्ट है।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री प्रहलाद जोशीः सर, जहां से भी ऐसी कम्प्लेंट आती है, भारत सरकार उस पर सख्ती से कार्यवाही करती है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा पीएसयूज़ के साथ कोयला प्रोडक्शन था, उसके कारण हमारा टोटल प्रोडक्शन was sufficient for 50 per cent of the requirement. Now, because we have completely stopped, the scam regime has been completely stopped, यह स्कैम रिजीम बंद होने के कारण हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ऑक्शन करके और इसमें प्राइवेट लोगों को शामिल करके देश की जो नीड है, एनर्जी और कोयले की रिक्वायरमेंट को पूरा करने जा रहे हैं। This is the Narendra Modi Government which believes in transparency. ...*(Interruptions)*... We believe in that and we are committed to that.

श्री उपसभापतिः क्वेश्चन नंबर 125.